

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO.7**  
TO BE ANSWERED ON 02/02/2024

**PRODUCTION OF WHEAT, RICE AND PULSES**

\*07. SHRI ANIL DESAI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the total production of wheat, rice and pulses in the country during last three years, year-wise;
- (b) the total domestic demand of the same during last three years, and whether demand is more than production in the country;
- (c) the quantity of the same being imported; and
- (d) the total demand and production of the same in the country after Covid pandemic?

**ANSWER**

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI ARJUN MUNDA)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN RESPECT OF PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 07 FOR 02/02/2024 REGARDING “PRODUCTION OF WHEAT, RICE AND PULSES”**

(a) to (d): The country witnessed a record foodgrain production of 3296.87 Lakh Metric Tonnes (LMT) during the agricultural year 2022-23 registering an increase of 30.82% as compared to 2520.25 Lakh Metric Tonnes (LMT) in 2014-15. Further, during 2022-23 the production of rice, wheat and pulses stood at 1357.55 LMT, 1105.54 LMT and 260.58 LMT respectively registering an increase of 28.7%, 27.77% and 51.90% over their respective production of 1054.82 LMT, 865.27 LMT and 171.54 LMT during 2014-15. The growing foodgrains production in the country is due to higher budget allocation to agriculture sector and successful implementation of various scheme and programmes by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

The budget allocated for Agriculture during the FY 2022-23 stood at Rs. 1,24,000.00 crore as compared to Rs. 22,652.25 crore in FY 2014-15, recording an increase of 447.41%.

National Food Security Mission (NFSM) aims to increase the production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement; restoring soil fertility and productivity; and enhancing farm level economy. During the year 2022-23, Rs. 1395.00 crores was allocated under NFSM. Rashtriya Krishi Vikas Yojana – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation (RKVY-RAFTAAR) targets at broad objectives of making farming a remunerative economic activity through strengthening the farmer’s effort, risk mitigation with major focus on pre & post-harvest infrastructure. During the year 2022-23, Rs. 3005.08 crore was allocated for RKVY.

Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan’ (PM-AASHA), is an umbrella scheme comprising Price Support Scheme (PSS) which is implemented for procurement of notified pulses, oilseeds and copra of Fair Average Quality (FAQ) at Minimum Support Price (MSP), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) and Private Procurement & Stockist Scheme (PPSS). Further, Government announces Minimum Support Prices (MSPs) for twenty-two (22) mandated crops. Government has increased the MSPs for all mandated Kharif, Rabi and other commercial crops with a return of at least 50 per cent over all India weighted average cost of production from the agricultural year 2018-19.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in 2016 in order to provide a simple and affordable crop insurance product to ensure comprehensive risk cover for crops to farmers against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest and to provide adequate claim amount. During the year 2022-23 under PMFBY, 1174.7 lakh farmers applications were enrolled and the funds allocated stood at Rs. 15500 crores. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is a central sector scheme under which financial benefit of Rs. 6000/- per year is transferred in three equal four-monthly instalments into the bank accounts of eligible farmers' families across the country, through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. The Government of India has disbursed over Rs. 2.81 lakh Crore to more than 11 Crore farmers.

The details of production of rice, wheat and various pulses during last three years are given as under:

Crop	Production (lakh tonnes)		
	2020-21	2021-22	2022-23
Rice	1243.68	1294.71	1357.55
Wheat	1095.86	1077.42	1105.54
Pulses	254.63	273.02	260.58
Total Foodgrains	3107.42	3156.16	3296.87

India, in recent years, has emerged as net exporters of agricultural products. It is the major rice exporting country in the World. During 2022-23, the export of rice stood at 223.47 lakh tonnes witnessing an increase of 86% in comparison to rice export of 120.01 lakh tonnes during 2014-15. Further, the import of pulses in the country witnessed a decrease by 46% in comparison to pulses import in 2014-15. During the year 2022-23, pulses import stood at 24.96 lakh tonnes, as against 45.85 lakh tonnes in the year 2014-15, depicting less reliance on imports due to increased domestic production.

The details of import of wheat, rice and pulses during last three years are as under:

Crop	Import (in thousand tons)		
	2020-21	2021-22	2022-23
Rice	4.76	10.58	6.71
Wheat	0.00	0.05	13.57
Pulses	2466.16	2699.69	2469.17

The Working Group constituted by National Institution for Transforming India (NITI) Aayog on Crop Husbandry, Agricultural Inputs, Demand and Supply Projections in its report "Demand & Supply Projections towards 2033 Crops, Livestock, Fisheries

and Agricultural Inputs” published in February, 2018 had projected the demand for terminal years 2016-17, 2017-18 and 2021-22.

The details of production and projected demand for aforesaid years are as under:

(in lakh tonnes)

Crop	2016-17		2017-18		2021-22	
	Demand	Production	Demand	Production	Demand	Production
Rice	1035.90	1096.98	1081.60	1127.58	1092.80	1294.71
Wheat	901.80	985.10	957.10	998.70	971.20	1077.42
Pulses	236.10	231.31	260.50	254.16	267.20	273.02

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 07  
02 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: गेहूं, चावल और दालों का उत्पादन**

**\*07. श्री अनिल देसाई:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में गेहूं, चावल और दालों का वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इनकी कुल घरेलू मांग कितनी-कितनी रही है, और क्या देश में इनकी मांग उत्पादन से अधिक है;
- (ग) इनका कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है; और
- (घ) कोविड महामारी के बाद, देश में इनकी कुल मांग और उत्पादन कितना हैं?

उत्तर  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘‘गेहूँ, चावल और दलहनों का उत्पादन’’ के संबंध में दिनांक 02.02.2024 को देय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 07\* के उत्तर के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): देश में कृषि वर्ष 2022-23 के दौरान 3296.87 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो 2014-15 में 2520.25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की तुलना में 30.82% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान चावल, गेहूँ और दलहन का उत्पादन क्रमशः 1357.55 एलएमटी, 1105.54 एलएमटी और 260.58 एलएमटी रहा, जो 2014-15 के दौरान उनके तत्संबंधित उत्पादन 1054.82 एलएमटी, 865.27 एलएमटी और 171.54 एलएमटी से 28.7%, 27.77% और 51.90% की वृद्धि दर्शाता है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि के लिए आवंटित बजट वित्तीय वर्ष 2014-15 में 22,652.25 करोड़ रुपए की तुलना में 1,24,000.00 करोड़ रुपए है, जो 447.41% की वृद्धि दर्शाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का लक्ष्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि; मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता का पुनर्जीवन; और कृषि स्तर की बचत को बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूँ और दलहनों का उत्पादन बढ़ाना है। वर्ष 2022-23 के दौरान एनएफएसएम के तहत 1395.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए लाभकारी पहल (आरकेवीवाई-आरएएफटीएआर) का लक्ष्य किसान के प्रयासों को सुदृढ़ करके, फसल पूर्व से फसलोपरान्त अवसंरचना पर विशेष बल देने से जोखिम कम करने के माध्यम से कृषि को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। वर्ष 2022-23 के दौरान आरकेवीवाई के लिए 3005.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक समग्र योजना है जिसके तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की अधिसूचित दलहनों, तिलहनों और खोपरा की खरीद के लिए लागू किया है, भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शामिल है। इसके अलावा, सरकार बाईस (22) अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवर और पर्याप्त दावा राशि सुनिश्चित किया जाना है। वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत, 1174.7 लाख किसानों के आवेदन नामांकित किए गए और आवंटित राशि रु 15500 करोड़ थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से, देश भर के पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान चार-मासिक किशतों में प्रति वर्ष 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ, अंतरित किया जाता है। भारत सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान चावल, गेहूँ और विभिन्न दलहनों के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

फसल	उत्पादन (लाख टन में)		
	2020-21	2021-22	2022-23
चावल	1243.68	1294.71	1357.55
गेहूँ	1095.86	1077.42	1105.54
दलहन	254.63	273.02	260.58
कुल खाद्यान्न	3107.42	3156.16	3296.87

हाल के वर्षों में, भारत, कृषि उत्पादों के निवल निर्यातक के रूप में उभरा है। यह विश्व का प्रमुख चावल निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान, चावल का निर्यात 223.47 लाख टन रहा, जो 2014-15 के दौरान 120.01 लाख टन के चावल निर्यात की तुलना में 86% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, 2014-15 में दलहनों के आयात की तुलना में देश में दलहनों के आयात में 46% की कमी देखी गई। वर्ष 2022-23 के दौरान दलहनों का आयात 24.96 लाख टन रहा, जबकि वर्ष 2014-15 में यह 45.85 लाख टन था, जो घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात पर निर्भरता में हुई कमी को दर्शाता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान गेहूँ, चावल और विभिन्न दलहनों के आयात का विवरण निम्नानुसार है:

फसल	आयात (हजार टन में)		
	2020-21	2021-22	2022-23
चावल	4.76	10.58	6.71
गेहूँ	0.00	0.05	13.57
दलहन	2466.16	2699.69	2469.17

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग द्वारा फसल उत्पादन, कृषि आदान, मांग और आपूर्ति अनुमान पर गठित कार्य समूह ने फरवरी, 2018 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट "फसल, पशुधन, मत्स्यपालन और कृषि आदान के लिए मांग और आपूर्ति अनुमान 2033" में आवधिक वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2021-22 के लिए मांग का अनुमान लगाया।

उपरोक्त वर्षों के लिए उत्पादन और अनुमानित मांग का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

फसल	2016-17		2017-18		2021-22	
	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन
चावल	1035.90	1096.98	1081.60	1127.58	1092.80	1294.71
गेहूँ	901.80	985.10	957.10	998.70	971.20	1077.42
दलहन	236.10	231.31	260.50	254.16	267.20	273.02

\*\*\*\*\*

SHRI ANIL DESAI: Sir, the Minister of Agriculture has given a very elaborate reply. In fact, I had asked very specific questions but going beyond the scope of the questions, the Minister has given a very elaborate reply.

In the answer which has been given, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been emphasized. During the year 2022-23, 11.75 lakh farmers' applications were enrolled and the funds allocated -- in a sense, it is taken as claims which were paid -- were to the tune of Rs. 15,500 crores. If we go by this, the PMFBY, which was introduced in 2016, it needed desperate improvement every year because the farmers' woes on the ground were never heard. If we go by the figure of 15,500 crore of rupees by way of claims given to the farmers, average farmer gets around Rs. 1,320. The amount which the farmer pays by way of premium comes to 2 per cent of the Kharif crop and 1.5 per cent of the Rabi crop. On an average, an amount of more than 5,000 rupees is paid by the farmer. The Government's answer talks about PMFBY on which a lot of emphasis has been made. Sir, the Government has been saying it with pride that over the years, it has been very beneficial for the farmers but it is not a fact. On the ground, farmers are crying and you can verify the facts from the insurance companies and the Government department, and more than anything, from the farmers themselves.

MR. CHAIRMAN: Supplementary, please.

SHRI ANIL DESAI: May I know from the hon. Minister as to what improvements are being made or have already been done so that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) becomes an effective instrument in the hands of the Government to give benefits to the farmers?

**सुश्री शोभा कारान्दलाजे :** सभापति जी, भारत की फसल बीमा योजना 2016 में नयी पॉलिसी के तहत शुरू हुई। This is the largest crop insurance scheme in the world in terms of farmers' registration. Also, this is the third largest scheme in the world in terms of insurance premiums. हमारे देश में 7 सालों में 49.44 करोड़ किसानों ने application enroll की है और इस साल 14.06 करोड़ applications आयी हैं। इसमें 7 सालों में किसानों ने 29,183 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा है। Claims received - Rs. 1,46,664 crore, यानी claims मिलने में बहुत ज्यादा गुना बढ़ोतरी हुई है। हर साल यदि किसी किसान ने 100 रुपये भरे, तो Government of India स्टेट को मदद देती है। इसमें तो पूरी की पूरी स्टेट ही इसकी implementing agency है। भारत सरकार अपना हिस्सा स्टेट को देती है। स्टेट टेंडर मँगाती है, स्टेट ही इसका implementation करती है और भारत सरकार का हिस्सा उसको मिलता है। इस प्रकार यदि

किसानों ने 100 रुपये pay किये तो अभी तक 502 रुपये किसानों को मिले हैं, इसीलिए 29,000 करोड़ के लिए 1,46,000 करोड़, they got the claims under Fasal Bima Yojana. सभापति जी, हम इसमें नयी फसल बीमा योजना की नीति लाये हैं। इसमें अगर किसी को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होता है, तो उसको क्लेम देने के लिए हमने एक नयी पॉलिसी बनायी है। हमने टेंडर प्रक्रिया को तीन साल के लिए बढ़ाया है। ऐसे ही जो स्वेच्छा से खुद प्रीमियम भरना चाहते हैं, वे भर सकते हैं। यह कम्पल्सरी नहीं है, बल्कि स्वेच्छक है। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, सॉफ्टवेयर का यूज किया है। इस संबंध में राज्य सरकार जो करना चाहती है, उसके हिसाब से वह कर सकती है और भारत सरकार इस मद में अपना हिस्सा देती है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI: Sir, for my first supplementary, I would request the hon. Minister to go through the answer and please answer correctly because the answer which has been given is completely wrong. The explanation given by the hon. Minister does not satisfy me or my expectations because I have different figures with me.

**सुश्री शोभा कारान्दलाजे:** सर, वह गलत नहीं है, बल्कि सही है।

SHRI ANIL DESAI: Sir, any way, my second supplementary is with respect to the figures regarding pulses which I asked in my question. In 2021-22, the projected demand in pulses was 267 lakh tonnes whereas the production during the same period was 273 lakh tonnes and the imports during the same time, which has been shown on the earlier page, were around 2699 thousand tonnes. May I know from the hon. Minister, through you, why has this anomaly or mistake taken place? Is it a mistake in the answer or when the production is higher than the demand, where is the question of importing pulses in that very year? How do you justify the need to go for import of pulses during 2021-22 when the production of pulses was much higher than the demand?

**सुश्री शोभा कारान्दलाजे:** सर, हमारे देश में तिलहन और दलहन की जितनी माँग है, उतनी पैदावार नहीं है, इसलिए हमें बाहर के देशों से इनका इम्पोर्ट करना पड़ता है। तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए किसानों को मदद भी दे रही है। हमें तिलहन और दलहन का एरिया बढ़ाना है, इसलिए हम उत्पादन और उत्पादकता, दोनों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हर साल दलहन की कमी का सामना कर रहे हैं, तुअर दाल की ज्यादा कमी का सामना कर रहे हैं। तुअर दाल की ज्यादा

उपज कर्णाटक और महाराष्ट्र में होती है।...**(व्यवधान)**...दलहन के संबंध में पूछा गया है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ..*(Interruptions)*.. Yes, hon. Minister.

**सुश्री शोभा कारान्दलाजे:** सर, हम तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए दलहन के 250 हब्स बनाये हैं। हम इसकी नई वैरायटीज के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। हम क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। आईसीएमआर इसके लिए रिसर्च कर रही है। हमने इसके लिए एमएसपी को बढ़ाया है। हम एमएसपी पर किसानों से इसको खरीदते हैं।...**(व्यवधान)**... एमएसपी देने से किसानों को लगता है कि हम जो फसल उगाते हैं, उसको सरकार एमएसपी पर खरीदती है।...**(व्यवधान)**... इसलिए हम एमएसपी को समय-समय पर बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से हम दलहन की पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं। हम इसका एरिया बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तुअर दाल की पैदावार में कमी है, क्योंकि कर्णाटक और महाराष्ट्र में इसकी पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन इन राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। इसके कारण तुअर दाल की पैदावार में कमी हुई है। हम तुअर दाल का इम्पोर्ट करके देश की माँग को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Supplementary number three, Dr. Ashok Kumar Mittal.

**डा. अशोक कुमार मित्तल :** सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों को दिया जाने वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोगुना कर दिया गया है, जो कि सराहनीय है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या भारत सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा):** माननीय सभापति महोदय, दलहन की कई किस्मों में से कुछ की पैदावार अधिक होती है, कुछ की कम होती है, जिसमें से तूर दाल के बारे में कहा गया है। यह सबकी जानकारी में है कि पिछली बार कर्णाटक में सूखे के कारण अच्छी फसल नहीं हो पाई और जो तूर दाल होती है, उसके उत्पादन में बहुत अधिक समय लगता है। चना दाल का उत्पादन अधिक है। देश में कुल दालों का जो उत्पादन हुआ है, उसके अनुसार वह सरप्लस है, लेकिन तूर दाल की जितनी आवश्यकता है, उसमें कमी आई है।

सर, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एमएसपी के बारे में माननीय मोदी जी की गारंटी है। किसानों की आय दोगुनी हो, उनकी लागत का लाभ अच्छे ढंग से मिले, यह अपने आपमें मोदी जी की गारंटी है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.